भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5513

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

एनएच-127 का निर्माण/उन्नयन

5513. श्री सालेंग ए. संगमा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रानी बाघमारा से रानीखो तक राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-127 के निर्माण और उन्नयन की स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है और इस परियोजना के लिए कुल कितना बजट आबंटित किया गया है और अब तक कितनी निधि जारी की गई है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-127 को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या भूमि अधिग्रहण अथवा पर्यावरणीय मंजूरी के कारण कोई विलंब हुआ है;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त निधि अथवा विशेष उपाय करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-127 के पूरा होने से स्थानीय समुदायों को संपर्क और आर्थिक विकास के संदर्भ में किस प्रकार लाभ होगा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) रानी बाघमारा से रानीखो खंड तक का हिस्सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्यीय राजमार्ग संख्या 4 है। परियोजना को छह पैकेजों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनमें से पांच परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष पैकेज संख्या 2 (नोंगजरी से महेशखोला) को 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) परियोजना के लिए कुल आबंटित बजट 1267 करोड़ रुपये है, जिसमें से अब तक 1075.83 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। परियोजना को 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और उपलब्ध सूचना के अनुसार, भूमि अर्जन या पर्यावरण मंजूरी के मुद्दों के कारण इसमें कोई विलंब नहीं हुआ है।

(घ) चूंकि परियोजना पूर्ण होने वाली है, इसलिए किसी अतिरिक्त निधि या विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) पूर्ण हो जाने पर यह परियोजना मेघालय के दो सुदूर जिलों - दक्षिण गारो हिल्स और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स को आपस में जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त, उन्नत सड़क अवसंरचना, परियोजना क्षेत्रों में निवासियों के लिए बाजारों, स्वास्थ्य परिचर्या और शैक्षिक केंद्रों तक पहुंच को सुगम्य बनाएगी, जिससे सुदूर क्षेत्रों का समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।

*****